जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 116 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 27 फरवरी, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

केजरीवाल राज्यसभा का सदस्य बनने की तैयारी में?

दिल्ली में आप की करारी हार के बाद, विशेषकर मु.मंत्री केजरीवाल की भी अपनी विधानसभा सीट की हार के बाद, कई तरह की अटकलबाजियाँ चल रही हैं, केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 फरवरी। आप ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिये राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को पार्टी प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। इससे राज्यसभा में पार्टी के संस्थापक अरविन्द केजरीवाल के राज्यसभा में सम्भावित प्रवेश की अटकलों को एक बार फिर बल मिला है।

अगर अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं, तो राज्यसभा की सीट खाली हो जायेगी तथा राज्यसभा के रिक्त स्थान को भरने की प्रक्रिया में करीब छः महीने का समय सम्भावित होता है। हाल ही में हुये दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली करारी चुनावी हार के बाद, यह संभव एवं संभावित है कि केजरीवाल राज्यसभा में प्रवेश की कोशिश करें, क्योंकि सांसद बनने के बाद, आप नेता को सामाजिक एवं राजनैतिक सरोकारों से संबंधित मुद्दे उठाने के लिये समुचित मंच मिल जायेगा सांसद बनने के बाद, केजरीवाल यह अपेक्षा की कर सकेंगे कि उन्हें, उनके खिलाफ चल रहे उन केसों में कुछ संवैधानिक संरक्षण भी मिल सकेगा, जिन केसों की जाँच -पड़ताल लॉ एन्फोर्समेन्ट एजेन्सियाँ कर रही हैं।

- एक प्रबल संभावना यह बताई जा रही है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सांसद के रूप में केजरीवाल ज्यादा अहम् भूमिका निभा सकते हैं, सामाजिक मुद्दों को हाईलाइट करने में।
- इस संभावना को और बल मिला है, जब से केजरीवाल के निजी मित्र, राज्यसभा सदस्य, संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई है।
- संजीव अरोड़ा, अभी पंजाब से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हैं। वे अगर उपचुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा और केजरीवाल को राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिल जाएगा।
- वैसे भी केजरीवाल के लिये पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि, पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में आप के 94 विधायक हैं, बनिस्पत दिल्ली के, जहाँ अब आप के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है।

पंजाब आप प्रवक्ता जगतार सिंह संघेरा ने इन अटकलों का खंडन किया है, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्यसभा सांसद बनने से केजरीवाल को यह मदद मिलेगी कि, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिये एक बड़ा मंच मिल जायेगा। उन पार्टी नेताओं का कहना है कि अब तक केजरीवाल के पास जो भी पद रहे हैं, वे सब उनके लिये सामाजिक कल्याण का साधन रहे हैं।

चूँकि आप दिल्ली में हार गई है, इसलिये केजरीवाल के भविष्य को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें चर्चा में हैं। ऐसी भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि वे भगवंत सिंह मान को हटाकर, पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।

आप के पास राज्यसभा की कुल 10 सीट हैं, जिनमें से 7 पंजाब से तथा 3 दिल्ली से हैं। चूँकि दिल्ली विधानसभा में आप बहुमत खो चुकी है, इसलिये दिल्ली से राज्यसभा में प्रवेश करने की कोशिश केजरीवाल के लिये नुकसानदायक हो सकती है। दूसरी तरफ, पंजाब में, आप के पास स्पष्ट तथा सुविधाजनक बहुमत है, क्योंकि विधानसभा की कुल 117 सीटों में से, 94 सीटें आप के पास हैं।

केजरीवाल के नजदीक माने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट से कुमारास्वामी को राहत नहीं मिली

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े भूमि विमुद्रीकरण मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और राजेश बिंदल की पीठ ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन के तहत छूट की मांग करने वाली कुमारस्वामी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा

- सुप्रीम कोर्ट ने, कुमारास्वामी पर उनके कार्यकाल से जुड़े भूमि डीमॉनिटाइज़ेशन मामले में अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

सकता। इस निर्णय से बनशंकरी में 02 एकड़ और 24 गुंटा भूमि के विमुद्रीकरण के संबंध में मुकदमे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसे 1997 में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। बाद में बीडीए की आपत्तियों के बावजूद 2010 में इस भूमि को निजी पक्षों को 4.14 करोड़ में बेच दिया गया था। यह मामला एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके कारण लोकायुक्त पुलिस ने भारतीय दंड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूक्रेन की जमीन के नीचे दबे खनिज को अमेरिका ललचाई नज़रों से देख रहा है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 फरवरी। यूक्रेन की युद्धग्रस्त धरती के नीचे भविष्य का खजाना छुपा है, जो वैश्विक सत्ता समीकरणों को नया आकार दे सकता है। यहां दुर्लभ खनिजों, लीथियम व टाइटैनियम के भंडार हैं। इस समय दुनिया में ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है, जिसमें हाईटैक युद्ध होंगे, इलैक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा जोर होगा। ये महत्वपूर्ण खनिज, पैट्रोल, डीजल बहुत महत्वपूर्ण बन गए है और टैक्नॉलजी व सैन्य सर्वोच्चता की मुख्य कुंजी हैं, इसलिए अमेरिका इन पर आधिपत्य चाहता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जैलेन्स्की शुक्रवार 28 फरवरी को निजी मुलाकात के लिए वॉशिंगटन आ सकते हैं तथा इस दौरान खनिज निकालने के समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

फाइनैंशियल टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज निकालने की डील की शर्तों पर सहमति हो गई है। कीव को यकीन है कि इससे अमेरिका की यूक्रेन के प्रति दूरगामी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का रास्ता साफ होगा।

समझौते के अंतिम प्रतिरुप, जो 24 फरवरी को तैयार हुआ है, में एक ऐसा कोष बनाने का प्रावधान है, जिसमें यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों जिनमें तेल और गैस भी शामिल हैं, के भावी मुद्रीकरण से 50 प्रतिशत राजस्व आवंटित करेगा, साथ ही संबंधित परिवहन सुविधा भी देगा।

एग्रीमैंट में उन खनिजों को शामिल नहीं किया गया है, जिनका राजस्व पहले ही यूक्रेन के बजट में जोड़ा जा चुका है, यानि यह समझौता नैफ्टोगैज़ और युक्रनाफ्टा में चल रही गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। अंतिम प्रारुप से 500 अरब डॉलर का रीकंस्ट्रक्शन फंड बनाने का प्रावधान हटा दिया गया है, जिसके तहत यूक्रेन को अपने खनिज उत्खनन राजस्व का 50 प्रतिशत स्थानान्तरित करना पड़ता और जिसमें अमेरिका अपना शतप्रतिशत वित्तीय हित बनाए रखेगा।

एग्रीमैंट में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी का कोई उल्लेख नहीं है। कीव ने शुरु में डील के एवज में यह गारंटी मांगी थी। इसमें अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे फंड में यूएस का हिस्सा और संयुक्त ओनरशिप के समझौते की शर्तों का उल्लेख नहीं है।

- हर देश भविष्य में विश्व में रुतबा बनाये रखने के लिए हाई-टैक हथियार, इलैक्ट्रिक्ल व्हिकल्स तथा अक्षय ऊर्जा पर अपना नियंत्रण बनाये रखना चाहता है। इन हाई-टैक हथियार व इलैक्ट्रिक वाहन आदि के लिये रेअर अर्थ मिनरल्स जैसी लीथियम, टाइटेनियम की आवश्यकता रहती है। यूक्रेन में भूमि के नीचे इन खनिजों का विपुल भण्डार है, जिसकी कीमत 500 बिलियन डॉलर आंकी जाती है।
- इसके अलावा यह भी सत्य है कि चीन के पास विश्व के लीथियम का 34 प्रतिशत लीथियम भण्डार है और रूस के पास टाइटेनियम की भी भारी सप्लाई है।
- अमेरिका, चीन व रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इन खनिजों के लिए। अतः यूक्रेन के इन खनिजों के भण्डार को जमीन से निकाल कर इण्डस्ट्रियल उपयोग में लेने में भारी रुचि रखता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

50 लाख डॉलर में खरीदी जा सकेगी अमेरिका की नागरिकता

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने दुनियाभर के अमीरों के लिए ''गोल्ड कार्ड'' स्कीम घोषित की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 फरवरी। अमीरों को अमेरिका में बसने के लिए आकर्षित करने हेतु अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने एक नई इम्मिग्रेशन पहल घोषित की है, जिसका लक्ष्य अमीर विदेशी निवेशक हैं। यह नीति है ''गोल्ड कार्ड'', जिसके तहत 50 लाख डॉलर के भुगतान पर अमेरिका की नागरिकता हासिल की जा सकती है।

ट्रम्प ने कहा, ''हम गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं, इस पर हम 50 लाख डॉलर की कीमत रखने जा रहे हैं।''

वर्तमान के ईबी-5 वीसा कार्यक्रम की जगह होने वाली यह नीति निवेशक को ग्रीन कार्ड की सुविधा देगी और वे निवेश के जरिए अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

मौजूदा ईबी-5 वीसा कार्यक्रम 1990 से शुरु हुआ था। इसके तहत उन विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकन नागरिकता का प्रावधान था, जो पूँजी निवेश के जरिए रोजगार सृजित करते थे या संरक्षित करते थे। इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1.05 मिलियन डॉलर थी तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह राशि 8 लाख डॉलर थी। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े की आशंका के चलते इस योजना की भारी आलोचना हो रही थी। बिज़नैस से जुड़े लोग, ट्रम्प परिवार के लोगों ने प्रॉपर्टी के काम में इसका इस्तेमाल किया है।

ट्रम्प ने कहा कि गोल्ड कार्ड, ग्रीन कार्ड की सुविधा देगा और यह अमेरिकन नागरिकता प्राप्त करने का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह योजना ईबी-फाइव वीसा कार्यक्रम की जगह लागू की जा रही है। ईबी-फाइव वीसा कार्यक्रम में 10.5 लाख डॉलर के निवेश और रोजगार सृजन पर ग्रीन कार्ड दिए जाने का प्रावधान था, तथा आर्थिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए निवेश की सीमा 8 लाख डॉलर ही थी।
- सूत्रों ने बताया कि ईबी-फाइव वीसा योजना का फर्जी तरीके से लाभ उठाकर ट्रम्प परिवार के लोगों ने प्रॉपर्टी डवलपमैंट में काफी पैसा लगाया था।
- ट्रम्प ने पत्रकारों के सवाल के एक जवाब में यह भी कहा कि रूस के अमीर भी यह गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं।

पुणे : सरकारी बस में महिला से दुष्कर्म

पुणे, 26 फरवरी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में राज्य परिवहन की एक खड़ी बस में एक व्यक्ति ने 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। बताया गया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ कई मामले में भी दर्ज किए गए हैं।

स्वरगेट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान दत्ता गाडे के रूप में हुई है,

- पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।

जिसके खिलाफ पहले से चोरी और चेन छीनने के मामले दर्ज हैं। स्वरगेट महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का सबसे बड़ा बस जंक्शन है।

पीड़िता के मुताबिक, वह मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे पैठण जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि उसकी बस दूसरे स्टैंड पर आ गई है। इसके बाद आरोपी पीड़िता को विशाल बस अड्डा परिसर के एक सुनसान हिस्से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दक्षिण के किसी राज्य की सीटें कम नहीं होगी, ''डीलिमिटेशन'' से'

अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों के ''डीलिमिटेशन'' से दक्षिण भारत के राज्य की संसद में सीटों की संख्या कम होने वाली चर्चा को निरर्थक बताया व ठण्डे छींटे देने देने का प्रयास किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 फरवरी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को शान्त करने की कोशिश की तथा दावे के साथ कहा कि दक्षिण के किसी भी राज्य, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, की संसदीय सीटें कम नहीं होंगी। ज्ञातव्य है कि एक दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा था कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो ''राज्य के ऊपर'' अनिश्चिता की ''तलवार'' लटकती रहेगी।

शाह ने तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुये कहा, ''मुख्यमंत्री (स्टालिन) और उनके पुत्र (उदयनिधि स्टालिन) कुछ मुद्दों को उभार कर तमिलनाडु की जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने संसद में यह बात स्पष्ट कर दी है कि जनसंख्या या अनुपात के आधार पर होने वाले संसदीय क्षेत्रों के नये सीमांकन से दक्षिणी राज्यों के लोकसभा सदस्यों की संख्या कम नहीं होगी।''

लेकिन शाह के इस आश्वासन में भी छल-कपट की एक पतली गली है। उन्होंने जोर देते हुये यह तो कहा है कि दक्षिणी राज्यों की एक भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उत्तरी भारत के किसी भी राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या उन राज्यों की वर्तमान सीट संख्या से ज्यादा नहीं होगी। उनके दावे से जो प्रश्न उभर कर सामने आता है, वो यह है कि अगर सीट संख्या परिवर्तित नहीं होनी है, तो परिसीमन की कवायद आखिर की क्यों जा रही है?

दक्षिण भारत के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि कोयम्बटूर, जहाँ गृह मंत्री ने एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया, में भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष बोलते हुये जो वक्तव्य दिया, वह अर्द्ध-सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है।

इस अवसर पर बोलते हुये, शाह ने द्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि तमिलनाडु में सरकार ने राष्ट्र-विरोधी तत्वों, ड्रग-तस्करों तथा अवैध खनन माफिया को खुली छूट दे रखी है।

मंगलवार को स्टालिन ने कहा था कि परिवार-नियोजन की नीतियों के सफल क्रियान्वयन के चलते, तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा था, ''अगर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाता है, तो तमिलनाडु के आठ सांसद कम हो जायेंगे। इसके कारण, संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जायेगा।''

स्टालिन ने ''एक्स'' पर लिखा था, ''तमिलनाडु का मुख्यमंत्री होने के नाते,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर दक्षिण भारत के राजनीतिज्ञों के मन में एक संशय अभी बरकरार है। इन लोगों की चिन्ता है, अगर यह मान भी लिया जाये कि दक्षिण भारत के राज्यों के सांसदों की संख्या में कोई कमी नहीं होती, पर, इसकी क्या गारंटी है, कि, उत्तर भारत के राज्यों से निर्वाचित होने वाले सांसदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

मोहन बिष्ट दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बनेंगे

नयी दिल्ली, 26 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। विधानसभा की ओर से 27 फरवरी के लिए आज जारी कार्यसूची में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रस्ताव करेंगी कि बिष्ट को उपाध्यक्ष चुना जाए। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का कैबिनेट मंत्री मनजिन्दर सिंह सिरसा समर्थन करेंगे। बिष्ट के उपाध्यक्ष चुनने के लिए विधायक अनिल कुमार शर्मा दूसरे प्रस्तावक होंगे और गजेन्द्र सिंह यादव उनका समर्थन करेंगे।

- 27 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके नाम का प्रस्ताव करेंगी तथा कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

तीन साल बाद यूक्रेन युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है: ट्रम्प की भूमिका महत्वपूर्ण रही

पर, एक चतुर व्यापारी की तरह ट्रम्प ने यह हासिल करने के लिये कई तरह की ''डील्स'' कीं व परम्परागत मित्रों में भेद पैदा किये और नये ''मित्र'' बनाये, नये रिश्ते कायम किये, विश्वसनीयता को भी दांव पर लगाकर

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 फरवरी। यूक्रेन में तीन साल से जो युद्ध चल रहा है, वो अब समाप्त होने जा रहा है। अपने दावों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी तरफ से समझौते कर रहे हैं।

पश्चिम की प्रमुख समाचार एजेंसियाँ रिपोर्ट कर रही हैं कि यूएसए और यूक्रेन के बीच एक महत्वाकांक्षी खनिज समझौता हुआ है, जो प्रभावी रूप से युद्ध के अंत की घोषणा करता है।

यूक्रेन के साथ, ट्रम्प एक ऐसा समझौता कर रहे हैं, जिसमें उसके विविध प्राकृतिक संसाधनों - तेल और गैस, टाइटेनियम और अन्य दुर्लभ खनिजों का विकास किया जाएगा, वर्तमान में इन खनिजों पर चीन की मोनॉपली है। यूक्रेन में चिन्हित संसाधनों में से 85 से अधिक वर्तमान में चीन में प्रोसैस होते हैं। यदि चीन इन खनिजों की आपूर्ति को रोकता है, तो यह अमेरिका के लिए कठिन हो सकता है।

इन खनिजों का मूल्य अनुमानित रूप से 100 बिलियन से 500 बिलियन तक हो सकता है और चीन के साथ अमेरिका के विवाद में यह एक बड़ी राहत प्रदान करेगा। इन खनिज संसाधनों तक अमेरिका की स्वतंत्र पहुँच, अमेरिका को, अधिक आक्रामक रूप से चीन को धमकी देने में मदद करेगी।

- उदाहरण के लिये, रूस के यूक्रेन की भूमि पर किये गये कब्जे का सत्यापन कर दिया, पहली बार अमेरिका ने यू.एन. के प्रस्ताव पर रूस व नॉर्थ कोरिया के साथ वोट किया।
- पहली बार, अमेरिका व यूरोपियन यूनियन यू.एन. प्रस्ताव में अलग-अलग खेमे में खड़े थे।
- अमेरिका व रूस की बढ़ती नज़दीकियों ने चीन की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चीन का सदा प्रयास रहा है कि रूस व अमेरिका के बीच दीवार खड़ी रहे तथा रूस चीन के नज़दीक रहे, बनिस्पत अमेरिका के। पर, यहाँ भी ट्रम्प दोनों के बीच ''खाई-सी'' बनाने में कामयाब रहे।

यूएसए के यूक्रेन के साथ समझौते को एक ''प्रोटेक्शन रैकट'' कहा जा रहा है। अर्थात् अमेरिका ने अब तक रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को जो मदद दी है, उसके हर एक डॉलर के बदले में अमेरिका 2 डॉलर के संसाधन लेगा। संसाधन समझौते से जो फण्ड आएगा, उसका उपयोग देश के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका की कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम मिलेगा।

अमेरिका और यूक्रेन द्वारा यूक्रेन की जमीन पर इन खनिजों के जॉइंट डवलपमैंट का अर्थ होगा- एक प्रभावी युद्धविराम और शत्रुता के अंत का संकेत। लग रहा है, जैसे ट्रंप बंदूक की नोक पर समझौते कर रहे हैं। डॉनल्ड ट्रम्प को कानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति कोई खास आदर नहीं है। इसलिए यह समझौता प्रभावी रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों पर रूस के दावों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है। इससे रूस के राष्ट्रपति को आक्रमण के उनके कृत्य के लिए कुछ हद तक क्षमादान भी मिल जाता है। इस स्थिति की, यूक्रेन पर यूएन के प्रस्ताव में पुष्टि की गई है, जिसमें रूस को आक्रांता के रूप में नहीं बताया गया है।

यह नीति से बिल्कुल उल्टा है। अमेरिका ने रूस और उत्तर कोरिया के साथ वोट किया है।

इसके अलावा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देशों और अपने पारंपरिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नासिक कुम्भ पर अलग बैठक की शिंदे ने

नासिक, 26 फरवरी। महाराष्ट्र के नासिक में भी जल्द ही कुंभ का आयोजन होने वाला है और ऐसे में कुंभ की तैयारी की समीक्षा और चर्चा के लिए सीएम देवेन्द्र फड़नवीस ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हालांकि, इसमें डिप्टी सी.एम. एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में दोपहर करीब 1 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।यहां आपको बता दें कि इस बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आज उनके तय कार्यक्रम के अनुसार, वे सिंधुदुर्ग जिले के दौरे पर हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने नासिक कुंभ की तैयारी के लिए नासिक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक की थी। शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने यह बैठक इसलिए की थी, क्योंकि वे जिले में एक रैली करने आए थे।

- वे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगे।